भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1701
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

1701. श्री आलोक शर्माः
श्री नलिन सोरेनः
श्री मनीष जायसवालः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री नव चरण माझीः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए वर्तमान इस्पात उत्पादन क्षमता और साथ ही प्रत्येक राज्य की संबंधित हिस्सेदारी/भागीदारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस्पात उत्पादन की वृद्धि में राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 की क्या भूमिका है;

(ग) वर्ष 2030 तक झारखंड सहित उक्त वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसपी 2017 देश में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में रणनीतिक उपयोग के लिए विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं के स्वदेशी उत्पादन को सुनिश्चित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी इस्पात संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) देश में वर्तमान क्रूड इस्पात की क्षमता 218.89 मिलियन टन है। इसमें झारखंड और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी क्रमशः 10.82 और 0.82 प्रतिशत है।

(ख) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल सृजित कर सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, इस्पात संयंत्र की स्थापना आदि जैसे निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 सरकार और इस्पात क्षेत्र को एक तकनीकी रूप से उन्नत तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग के तौर पर विकसित करने की दिशा में नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देती है। सरकार ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में रणनीतिक अनुप्रयोग हेतु विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना) प्रारंभ की है।

*****